Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

मीडिया रीलिज

झारखण्ड में सड़कों की स्थिति सुधरेगी
रु. 530.53 करोड़ के 82 कार्य चल रहे हैं

श्री कमल नाथ एवम् श्री परिमल नथवाणी के बीच झारखण्ड के विकास पर चर्चा

रांची : जनवरी 5, 2011 : झारखण्ड राज्य से गुजरते राष्ट्रीय राजमार्गों एवम् राज्य की अन्य प्रमुख सड़कों की स्थिति में जल्द ही सुधार होगा। इनमें वामपंथी अंतिमवादियों से ग्रस्त इलाकों की सड़कें भी शामिल हैं। एक अधिकृत सूचना के तहत इस बात की पुष्टि हुई है। केन्द्रीय सड़क परिवहन एवम् राजमार्ग मंत्री श्री कमल नाथ ने प्रदेश के राज्य सभा सांसद श्री परिमल नथवाणी को झारखण्ड के विकास के बारे में आपसी विचार-विमर्श के दौरान यह जानकारी दी। श्री नथवाणी जब भी मौका मिलता है किसी भी व्यक्ति या मंच के समक्ष झारखण्ड के विकास का प्रश्न अवश्य उठाते हैं।

झारखण्ड में कुल 1844.07 किलोमीटर लम्बाई के बारह राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नवम्बर 30, 2010 को राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू (ऑन गोईंग) कार्यों के तहत राज्य में रु. 530.53 करोड़ के 82 कार्य चल रहे थे, ऐसा इस जानकारी में श्री कमल नाथ द्वारा श्री नथवाणीजी को बताया गया। सड़कों को चौड़ा करना तथा मजबूत बनाना, इनकी सवारी गुणवत्ता में सुधार, प्रमुख एवम् गौण पुलों व पुलिया का निर्माण आदि किस्म के विभिन्न कार्य इनमें शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 80 को छोड़कर, झारखण्ड में तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों को दो/चार लेन का बनाने का कार्य भी इनमें शामिल है। ये कार्य नैशनल हाइवे डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एन.एच.डी.पी.) या झारखण्ड में वामपंथी अंतिमवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास की रोड़ रिक्वायरमेन्ट प्लान (आर.आर.पी.) के अंतर्गत चल रहे हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 80 के शेष 73 किलोमीटर लम्बाई की सड़क को दो लेन में परिवर्तित करने का कार्य वर्तमान वार्षिक योजना 2010-11 में शामिल है। इसकी अनुमानित लागत रु. 57.23 करोड़ है। 64 किलोमीटर लम्बाई के टुकड़े को (जो 197 किलोमीटर से 260 किलोमीटर के बीच में पड़ता है जिसमें साहिबगंज बाई-पास भी आ जाता है) दो लेन में परिवर्तित करने की अनुमानित लागत ही रु. 50 करोड़ है। इसी प्रकार, वर्तमान 2010-11 की वार्षिक योजना में रु. 4.50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 80 पर आठ किलोमीटर की लम्बाई पर (205 किलोमीटर, 206 किलोमीटर तथा 220 से 225 किलोमीटर) सवारी गुणवत्ता सुधार कार्य-योजना ली गई है।

आगे यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 80 पर ही 261 से 282.9 किलोमीटर तक के 22.9 किलोमीटर लम्बाई का टुकड़ा दो लेन करने के लिए चौड़ा करने और मजबूत करने हेतु वार्षिक योजना में बजट प्रावधान कर के झारखण्ड की विशेष परियोजनाओं में इसे शामिल किया गया है। इसके लिए, श्री कमल नाथ के अधीनस्थ मंत्रालय ने रु. 52.81 करोड़ की अनुमानित राशि को मंजूर किया था। इनके अलावा, वार्षिक योजना 2010-11 में अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए प्रस्तावित कार्यों में रु. 20 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 23 पर गुमला बाई पास का कार्य एवम् राष्ट्रीय राजमार्ग 78 के कार्य भी सम्मिलित हैं।

वामपंथी अंतिमवादियों से असरग्रस्त इलाकों में राज्य की सड़कों के विकास के लिए लतेहार, पलामू, छतरा, लोहारदागा, गुमला, गरवाह, हजारीबाग और पूर्व सिंहभूम क्षेत्रों में रोड़ रिक्वायरमेन्ट योजना के तहत 248 किलोमीटर की राज्य की सड़कें चुनी गई हैं। राज्य सरकार द्वारा इसकी अनुमानित लागत का ब्यौरा केन्द्र को सौंपना बाकी था। इसके अलावा, रोड़ रिक्वायरमेन्ट योजना के अंतर्गत राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्गों के 248 किलोमीटर की सड़कों का विकास भी किया जाएगा। ये कार्य मुख्य रूप से छतरा, गरवाह, लतेहार, लोहारदागा और पश्चिम सिंहभूम में हैं। वामपंथी अंतिमवादियों से ग्रस्त इलाकों से गुजरते विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल 431.79 किलोमीटर की लम्बाईयों को रु. 528.87 करोड़ की लागत से चौड़ा करने तथा मजबूत करने हेतु रोड़ रिक्वायरमेन्ट योजना के तहत शामिल किया गया है।

अब तक झारखण्ड में नैशनल हाईवे डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स (एन.एच.डी.पी.) के अंतर्गत कुल बारह परियोजनाएं चल रही हैं जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। ये कार्य मुख्य तौर पर सड़कों

को चार-लेन या छ-लेन का बनाना तथा दो-लेन से ऊपर की सड़कों की शोल्डरिंग करना शामिल हैं। राष्ट्रीय राज्यमार्ग नं. 33, नं. 2, नं. 75, नं. 23, नं. 6 और नं. 32 के कतिपय हिस्सों में यह कार्य चल रहा है।

झारखण्ड में केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यों के अंतर्गत सेन्ट्रल रोड़ फण्ड (सी.आर.एफ.) के तहत रु. 266.73 करोड़ के कुल 23 कार्य मंजूर किये गये हैं। इनमें से आठ कार्यों को पूरा कर लिया गया है और शेष 15 प्रगति की राह पर हैं। पूर्ण हुए कार्य प्रमुख तौर पर धनबाद, खूंटी, हजारीबाग, चैबासा, रांची, डाल्टोगंज और देवघर डिवीजन के अंतर्गत हैं।

झारखण्ड सरकार ने बोकारो जिले में तीन सड़कों को चौडा करने और मजबूत करने का प्रस्ताव आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए भेजा था। केन्द्र ने इस सिफारिश पर सी.आर.एफ. (स्टेट रोड़) नियमावली 2007 के मद्दे नजर विचार करेगा। इस नियमावली के नियम 7(2) के अधीन, केवल राज्य के राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कों पर ही आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के अंतर्गत विचार किया जाता है।

संक्षेप में, श्री नथवाणीजी के मुताबिक केन्द्र एवम् राज्य सरकार दोनों ने सड़कों के विकास जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी सविधा के मुद्दे पर सोच कर अपनी सूझ-बूझ की मिसाल पेश की है जिससे आनेवाले दिनों में प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने और प्रदेश का विकास करने का एक नया और सकारात्मक आयाम निश्चित ही उपलब्ध होगा।

★ ★ ★